

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशोष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग :

देहरादून : दिनांक : 5 सितम्बर, 2006

विषय: रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में शासनदेश संख्या 25-दो(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 17.8.2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत रु० 6,91,35,000/- के आगणन के विरुद्ध स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रु० 1,41,35,000/- (रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार मात्र) में से रुपये 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विस्तरेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) इस धनराशि के पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगामी किशत की स्वीकृति दी जायेगी ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण चार समान किशतों में किया जाय एवं पूर्व स्वीकृत किशत के 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त ही आगामी किशत का कोषागार से आहरण किया जायेगा ।
- (5) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतल-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (7) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (8) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

- (9) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत जावव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसको एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय ।
- (10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-590/XXVII(5)/2006, दिनांक 26.9.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)

सचिव ।

संख्या-41-दो(1)/XXXVI(1)/2005-198-दो/02-तदुदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
4. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-37, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल-निगम, ऊधमसिंहनगर ।
5. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
6. एन०एच०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।